वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबशार अहमद) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की शाखायें खोलने के लिये कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि, सातवीं पंचवर्षीय योजना के साथ समाप्त शाखा लाइसेंसिंग नीति 1985–90 के दौरान गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखायें खोलने के वास्ते 109 लाइसेंस जारी किये गये थे। इसके अतिरिक्त गुजरात में शाखायें खोलने के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 144 केन्द्र आवंटित किये गये थे।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आवंटित केन्द्रों का जिलेवार ब्यौरा निम्नलिखित है:–

जिले का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आवंटित केन्द्र
1. अहमदाबाद	—
2. अमरेली	14
3. वलसाड़	21
4. बनासकंठा	4
5. भावनगर	14
6. डेंगा	4
7. गांधीनगर	2
8. भरूच	11
9. जामनगर	—
10. खेड़ा	—
11. जूनागढ़	18
12. कछ	2
13. मेहसाणा	3
14. पंचमहल	5
15. साबरकांठा	25
16. राजकोट	5
17. सूरत	4
18. सुरेन्द्र नगर	12
19. बडोदरा	—
कुल :	144

(ग) गुजरात में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निवेशित प्रति व्यक्ति राशि राष्ट्रीय औसत 249 रुपये की तुलना में 327/– रुपये थी।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के माध्यम से उद्योगों की सहायता करना

2558. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास के लिये कोई सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह सहायता देश भर को दी गई सहायता का कितने प्रतिशत है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के माध्यम से कानपुर के उद्योगों की सहायता के लिये क्या प्रयास किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) जी, हां । भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), एस.एफ.सी./एस.आई.डी.सी. और बैंकों के माध्यम से अपनी पुनर्वित्त योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश में लघु क्षेत्रों के उद्योगों के विकास के लिये सहायता प्रदान करता रहा है । इसके अतिरिक्त यह उपस्कर और संघटकों के लिये बिल पुनर्भुनाई योजनाओं, प्रत्यक्ष बट्टा योजना के तहत सहायता और आधारभूत सुविधाओं, अनुषंगी और उप संविदा इकाइयों के विपणन के विकास के लिये भी प्रत्यक्ष सहायता देता रहा है । 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में सिडबी द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत इकाइयों को मंजूर की गई समग्र सहायता और अखिल भारतीय प्रतिशतता नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपये)

		अखिल भारत के जोड़ की तुलना में प्रतिशतता
1991-92	216.96	7.52%

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(घ) सरकार अप्रत्यक्ष रूप से सिडबी को अपने संसाधन जुटाने के लिये सहायता करती है । यह क्षेत्र-विशिष्ट के उद्योगों को सहायता प्रदान नहीं करती है ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्यकरण की समीक्षा

2559. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जमा राशियों और निवेश राशियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की लगातार समीक्षा करते रहते हैं । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित मुख्य मुद्दा उनकी कमजोर अर्थक्षमता है जो राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के पंचाट और समीकरण समिति की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के वेतनमानों में हुए संशोधन के कारण और भी गंभीर हो गया है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर गठित कार्य दल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा की थी और उनके प्रचालन में सुधार लाने हेतु कुछ उपाय सुझाए थे । हाल ही में, वित्तीय प्रणाली पर समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में उन्होंने सिफारिश की है कि अर्थक्षमता को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी प्रकार के कार्यकलापों को करने की अनुमति दी जानी चाहिए तथापि, उनका फोकस लक्ष्य समूहों पर टिका रहना चाहिए । इसके अलावा, समिति ने यह भी सिफारिश की है कि एक तंत्र तैयार किया जाए जिसके